[Shri M. Kadershah]

Sir, I would like to submit that the southern part of the country experienced severe cyclone and flood recently. If these fund collections are to serve some purpose of a common cause, it can be appreciated but here we see that funds are collected for some leaders to conduct some Kisan Divas or something else. Sir, the student community whose future is a sea of suspense is annoyed at such political extravagance. I would like to know from the hon. Minister whether the students were forced to collect funds for presentation of a purse and I would also like to know how the Government proposes to satisfy the simmering discontent among the students.

SHRI CHARAN SINGH: I have nothing to add to what I have already said.

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : मैं आपको एक बात खाली कहना चाहता था कि आरक्षण की नीति का हम समर्थन करते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे गृह मंत्री ने इस बात का जोरदार समर्थन किया लेकिन एक बात उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आरक्षण से जो लोग जाते हैं उनके दिल में कोई ऐसी भावना हो सकती है कि उन वर्गों के प्रति वे संवेदनशील हों जहां से वे आते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यही बात दूसरे वर्गों के प्रति भी कही जाती है। जो लोग दूसरे वर्गों से आते हैं वे हमेशा . . .

श्री उपसभापति : स्पेशल मेंशन, श्री रामानन्द यादव।

श्री श्याम लाल यादव : वे हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं . . . *(Interruptions)* होना चाहिए मेरा यह निवेदन है . . .

(Interruptions)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : जाति को तोड़ना है। जाति तोड़ो आन्दोलन के द्वारा, जाति को तोड़ने के लिए सरकार के कदमों के अलावा और कोई रास्ता अपनाना जरूरी नहीं है। यह जो जाति भ्रम है इसका एक ही उपाय है . . .

(Interruptions)

श्री रामानन्द यादव : जात-पात का पूरा प्रचार कीजिए . . .

(Interruptions)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : कोई दूसरा उपाय नहीं है . . .

(Interruptions)

SHRI PIARE LALL KUREEL URF PIARE LALL TALIB; Sir, I wanted to say about it; I know the whole thing ...

श्री उपसभापति : ठीक है आप बहुत जानते हैं। लेकिन आपको जरा नियमों के अनुसार चलना चाहिए। श्री रामानन्द यादव।

SHRI PIARE LALL KUREEL URF PIARE LALL TALIB: How was permission given to Mr. Anand?

REFERENCE TO ALLEGED LATHI-CHARGE ON PEACEFUL PROCESSION IN PATNA

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : उपसभापति महोदय, 14 तारीख को अखिल भारतीय पिछड़े वर्ग के तत्वाधान में पटना के गांधी मैदान से एक जुलूस निकला। यह जुलूस सरकार से यह मांग कर रहा था कि पिछड़ी जातियों को 26% प्रान्तीय और केन्द्रीय नौकरियों में संरक्षण दिया जाए। यह जुलूस बड़े ही शान्तिपूर्ण ढंग से जा रहा था। इस जुलूस को विधान सभा से 1/4 मील की दूरी पर टरमीनेट कर दिया गया। वहां पर मीटिंग हुई। मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुआ। इस जूलूस के लिए सरकार से पहले इजाजत ले ली गई थी। उस प्रोसेशन में जो नारा था वह सरकार के अनुकूल था। नारा लगाया जा रहा था कि आरक्षण की व्यवस्था जो केबिनेट

के द्वारा, जनता पार्टी के मेनीफेस्टो के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के द्वारा कि संविधान में यह प्रावधान है बिल्कुल ठीक है, उसके खिलाफ नहीं हैं, उसको दिया जाए। यह भी कहा जा रहा था कि कर्पूरी ठाकुर आप घबराइये मत, हम लोग आपके साथ हैं। उस प्रोसेशन, उस मीटिंग को तोड़ने के लिए, तितर-बितर करने के लिए सी० आर० पी० के जवानों ने लाठी चार्ज किया और करीब 300 आदमी गिरफ्तार हुए। आज 22 आदमी हास्पीटल में हैं और अनेकों घायल हुए हैं। प्रजातन्त्र का नाम लेने वाली यह सरकार शान्तिपूर्ण प्रोसेशन पर लाठी चार्ज करती है। दूसरी बात, इस आन्दोलन के खिलाफ कि आरक्षण न दिया जाए इसके लिए जैसा कि आपने सुना विद्यार्थी परिषद् के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर में विद्यार्थियों ने केन्द्रीय मंत्री श्री जार्ज फर्नेंडीज साहब को बोलने नहीं दिया। उनकी कार पर पथराव किया, गाड़ी को डैमेज किया और इस कारण

I P.M.

से पीछे के दरवाजे से उनको भागकर बाहर जाना पड़ा। यह सब विद्यार्थी परिषद् के विद्यार्थियों ने किया। लोकनायक जयप्रकाश के अमृत महोत्सव पर जब उनको चांदी साने का अमृत 10 लाख का दिया जा रहा था या शायद उससे अधिक का, उस समय जैसा कि मंडल जी ने स्वीकार किया कि इन्हीं विद्यार्थी परिषद् के विद्यार्थियों ने, आरक्षण के विरोधियों ने, वहां पर आरक्षण के खिलाफ नारे लगाए। श्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री को उस मीटिंग में नहीं जाने दिया गया और इतना ही नहीं श्री कर्पूरी ठाकुर भी उस मीटिंग में नहीं पहुंच सके। लेकिन इस तरह के काम करने वाले लोगों पर बिहार की सरकार किसी तरह का अंकुश नहीं लगा सकी। फिर आप देखें, उपसभापति महोदय, कि किस तरह बिहार की जनता पार्टी के दलगत झगड़े हैं। आज उस मंत्रिपरिषद् का एक भाग यह चाहता है कि आरक्षण न हो और दूसरा चाहता है कि आरक्षण हो। फिर आपने यह भी देखा कि किस तरह जब गवर्नर साहब भाषण दे रहे थे उस वक्त जनता पार्टी के विक्रम कुंवर और श्री मुनिभाई चौबे ने तथा दूसरों ने आरक्षण की बात कही और गवर्नर जब उस लाइन को पढ़ने लगे तो हल्ला किया . . . *(Interruptions)* आपकी पार्टी तो उसमें शामिल है *(Interruptions)*

हम तो आपका समर्थन कर रहे थे इस ईश्यू पर *(Interruptions)* मैं यह कह रहा था कि एक तरफ इस आन्दोलन *(Interruptions)* जो लोग पीसफुल डिमांस्ट्रेशन करने वाले थे एक तो गवर्नमेंट सिन्सियर पर नहीं है। बिहार की सरकार यह नहीं चाहती कि आरक्षण हो क्योंकि अगर चाहती तो यह मुट्ठी भर लोग जो सदियों से सामाजिक और आर्थिक अधिकार लेकर बैठे हैं, इनकी कोई बात न सुनकर आरक्षण जल्दी करती। इस बात को सरकार भूले नहीं कि अगर यह पिछड़ा वर्ग, विशाल हाथी, कहीं खड़ा हो गया तो सचमुच ये विरोध करने वाले लोग कहीं नहीं रहेंगे। जनता पार्टी ने जो चुनाव जीता है वह पिछड़ी जातियों, हरिजनों और मुसलमानों के वोट पर ही जीता है। यह जो जामा मस्जिद के आपके मददगार हैं इन्होंने पटना की एक मीटिंग में खुलेआम कहा कि सरकार पिछड़े वर्गों, हरिजनों और मुसलमानों के वोट पर जीतकर आयी है इसलिए अगर जनता सरकार पिछड़े वर्गों के लिए, मुसलमानों के लिए, हरिजनों के लिए, आदिवासियों के लिए, क्रिश्चियन के लिए और इसके अलावा दूसरी माइनारिटीज केलिए कुछ नहीं करेगी तो वह एक दिन टिकने वाली नहीं है। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि इस तरह के हंगामा करने वाले लोगों से यह सरकार जरा भी भयभीत न हो और मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार क्लीयर कट

[श्री रामानन्द यादव]

इंस्ट्रक्शन बिहार सरकार को दे कि कांस्टीट्यूशन के द्वारा संविधान में जो पिछड़ी जातियों के संरक्षण की बात है उसको वह जल्दी से जल्दी लागू करे। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में जायज बताया है। इस आरक्षण के खिलाफ लोगों ने केस भी किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इसको सही बताया था। मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के मैनीफेस्टो में भी जो आरक्षण देने की बात कही गयी है उसको वह पूरा करे। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह किसी भी तरह इस तरह के आंदोलनों के फेर में न पड़कर आरक्षण को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करे। यही मेरी मांग है और दूसरी बात यह है कि इस तरह के जो पीसफुल प्रदर्शन करने वाले लोग है, जो पार्टियां है जिनके लोग सर्विसेज में नहीं हैं उन निहत्थों पर इस तरह से लाठियों और डंडों से प्रहार करना आंदोलन कुचलना नहीं है बल्कि यह जन आंदोलन ऐसा है जिसके बल से सरकार को यह ताकत होती है कि वह जनता के उपयोग के जो काम हैं उसको करे। इस प्रकार के प्रदर्शन जो जनता सरकार के कामों में होते हैं उस मदद को सरकार को लेना चाहिए।

SHRI PIARE LALL KUREEL URF PIARE LALL TALIB (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, kindly give me only two minutes.

श्री उपसभापति : किस बात पर बोलना चाहेंगे ?

श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब : रिजर्वेशन के मसले पर।

श्री उपसभापति : रिजर्वेशन पर बहस नही हो रही है।

श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब : चंद बातें कहना चाहता हूं।

(*Interruptions*)

SHRI L. R. NAIK (Karnataka): Give me one minute, Sir.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAMKRIPAL SINHA): Are you going to create a new precedent, Sir.

श्री उपसभापति : अब बहस नहीं होगी। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House adjourned for lunch at six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at six minutes past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman,** in the Chair.

THE BUDGET (GENERAL) 1978-79 GENERAL DISCUSSION—Contd.

SHRI P. RAMAMURTI (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, as far as this Budget is concerned, quite apart from the people on the Opposition side, even the Members of the Janata Party in their private party meetings have expressed their extreme dissatisfaction with the proposals. I am sure if a free vote is taken in this House the Budget will be thrown out by this House. This is the actual position. Now, I want to judge this Budget on the basis of what the Government of India itself had said in its Economic Survey in the concluding paragraph of Chapter I. It says:

"To sum up, while there is sufficient cause for satisfaction in the performance of the economy in the current year, the shortfalls in the production of commodities like edible oils, pulses and cotton, the low rate of increase in industrial production, the increased liquidity in the economy, the sluggishness in industrial investment and the accumulation of reserves are matters for concern. The emphasis of policy will therefore, have to be on increasing the output of these commodities,